भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1732

दिनांक 08.03.2016/ 18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

1732. **श्री जय प्रकाश नारायण यादव**:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के लिए समेकित कार्ययोजना के अंतर्गत जिला पुलिस बलों के आधुनिकीकरण करने और नए पुलिस थानों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और जिला पुलिस बल के आधुनिकीकरण करने एवं नए पुलिस थानों की स्थापना करने के लिए अब तक पृथक रुप से कुल कितनी निधि संस्वीकृत की गई/उपयोग में लायी गई; और

(ग) नक्सल प्रभावित जिलों विशेषकर बिहार में कार्यरत नए पुलिस थानों की संख्या कितनी है और इनमें तैनात पुलिस बलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क): **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्ति केन्द्रीय सहायता (एसीए) के नाम से पुनर्नामित एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) स्कूल भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक, स्वाराज्य केंद्र, पेयजल आपूर्ति, ग्राम सड़कें सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की रोशनियां आदि जैसी सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष**, 2009-10 **से** 2014-15 **तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वयनाधीन थी। इसमें जिला पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और नए पुलिस स्टेशन खोलने के लिए राज्यों को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। यह योजना वर्ष** 01.04.2015 **से बंद कर दी गई है।**

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।